

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह
आई

अपील संख्या 199/2022

रामप्रताप पुत्र घडसी, जाति जाट, निवासी ग्राम अजाडी कलां, तहसील व जिला झुंझुनूं (राज 0
आई

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
आई

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 प्रथम अपील खिलाफ
बअदालत तहसीलदार झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं मुकदमा उनवानी सरकार बनाम रामप्रताप, मु0न0 197
आदेश दिनांक 29.09.2022

उपस्थित:-

1. श्री राजेन्द्र सिंह बुडानिया, एडवोकेट- अपीलान्त की ओर से उपस्थित।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक- रेस्पोडेन्ट की ओर उपस्थित।

आदेश

दिनांक 13.0

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 29.09.20
विरुद्ध मय प्रा0प0 स्थगन एवं प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0
बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5
स्वीकार किया जाता है। अदालत मातहत ने अपीलान्त को जमीन खसरा नं0 91 रका 0.03 हैक्टर
गैर मुमकीन रास्ता व खसरा नं0 64 रकबा 0.09 हैक्टर स्थित ग्राम अजाडी कलां, तहसील झुं
अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने व 64 रूपये कक अर्थ दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित
उक्त आदेश से व्यथित होकर उक्त अपील अपीलान्त की ओर से नीचे लिखे अनुसार पेश की जा
अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर बहस खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली है। पटवारी हल्का
कलां द्वारा दिनांक 17.12.2021 को एकपक्षीय रूप से अपीलान्त की गैर हाजिरी में रिपोर्ट तैयार कर
हुई है। रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 17.12.2021 में नाजायज कब्जा के कॉलम में तारबन्दी करने क
अंकित कर पटवारी हल्का द्वारा अस्पष्ट व संदिग्ध रिपोर्ट पेश हुई है। पटवारी हल्का द्वारा तारबन्दी
जाने के संबंध में विशेष तथ्य व तारबन्दी किस बाबत की गई है उक्त तथ्य दर्ज नहीं कर अपूर्ण
बनाकर प्रस्तुत होने के बावजूद अदालत मातहत द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध गलत रूप से प्रकरण द
आदेश जैर बहस पारित किया है। अपीलान्त के विरुद्ध दफा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 19
प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अपीलान्त अतिक्रमी नहीं है। अपीलान्त द्वारा अदालत मातहत क
का जबाब प्रस्तुत किया गया है कि अप्रार्थी ने गत खसरा नं0 219 तादादी 20 बीघा 3 बिश्वा में
बीघा 10 बिश्वा खाम जमीन तारूराम पुत्र गणपतराम से दिनांक 26.06.1968 को जरिये रजिस्टर्ड विक
खरीदी थी। गत खसरा नं0 219 की जो सीमा थी वह सीमा आज भी कायम है। अप्रार्थी ने जो भूमि
की थी व विक्रेता ने जिसका कब्जा अप्रार्थी को दिया था उसी भूमि पर अप्रार्थी भूमि खरीदने से लेकर
दिनांक तक कायम है। अप्रार्थी ने कभी कोई सीमा अपने खेत की नहीं बढ़ाई। गत खसरा नं0 2
अप्रार्थी व तारूराम ने विभाजन कर लिया तथा विभाजन के बाद हाल खसरा नं0 92 रकबा 0.81
अप्रार्थी के खातेदारी काश्तकार में दर्ज चला आ रहा है। अप्रार्थी की इस खातेदारी जमीन की उत्तरी

मे कदीमी रास्ता था जो राजस्व रिकार्ड मे खसरा नं० 91 गै०मु० रास्ता के रूप मे दर्ज है तथा मौके पर आज भी वहीं कायम है। अप्रार्थी ने हाल खसरा नं० 91 गै०मु० रास्ते की भूमि पर कभी भी अतिक्रमण नहीं किया है तथा रास्ते पर ही कभी अतिक्रमण नहीं किया है तो जोहड पर अतिक्रमण नहीं किया है तथा रास्ते के पश्चिम मे गै०मु० जोहड खसरा नं० 64 स्थित है। जब अप्रार्थी ने रास्ते पर कभी अतिक्रमण नहीं किया है तो जोहड पर अतिक्रमण करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्योंकि जोहड की भूमि से पहले अप्रार्थी की भूमि की ओर उक्त खसरा नं० 91 रास्ता पडता है। पहले अप्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नं० 92 की उत्तरी व पश्चिमी सीमा पर बाड थी जिसे हटाकर अप्रार्थी ने अपने खेत के चारों तरफ रास्ते की तरफ अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि मे पशुओं से अपनी काश्त को बचाने के लिए तारबन्दी कर रखी है तथा अप्रार्थी की कृषि भूमि हाल खसरा नं० 92 रकबा 0.81 हैक्टर की खातेदारी जो अप्रार्थी के नाम दर्ज है। अप्रार्थी की खातेदारी जमीन की कोई नपति पटवारी हल्का द्वारा नहीं की गई तथा पटवारी हल्का ने जानबूझकर इरादतन अप्रार्थी को हैरान व पेशान करने की गर्ज से पटवार घर मे बैठकर गलत व झूठी रिपोर्ट तैयार की है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाब नोटिस व जबाब मे वर्णित बिन्दू सीमा विवाद के विषय को नजरअंदाज कर आदेश जैर बहस पारित किया गया है। आदेश जैर बहस स्पीकिंग नहीं है। आदेश जैर बहस के आधार पर मनमाने है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एकपक्षीय है जो साबित भी नहीं की गई है। अपीलान्ट ने किसी प्रकार से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट के स्वयं के खेत की सीमा पर खेत की सुरक्षा के लिए तारबन्दी कर रखी है। अपीलान्ट द्वारा पूर्व से रही सीमा पर तारबन्दी की गई है। अपीलान्ट की मौजूदगी मे पटवारी हल्का ने तथाकथित अतिक्रमण स्थल का कोई नाप नहीं किया है। तथाकथित नाप एकपक्षीय है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत के आदेश जैर बहस दिनांक 29.09.222 को अपास्त किया जावे। अपीलान्ट विकल्प मे यह निवेदन करता है कि अदालत मातहत को आदेश दिया जावे अपीलान्ट के खेत व खसरा नम्बर 91 व 64 के मध्य की सीमा का अपीलान्ट की उपस्थिति मे सीमाज्ञान किया जाकर अपीलान्ट को सीमाज्ञान की प्रति देकर सूचित किया जावे जिससे अपीलान्ट मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट व नपति के आधार पर स्वयं के खेत की सीमा पर तारबन्दी कर सके।

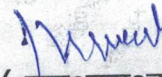
बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि पटवारी हल्का अजाडी कलां द्वारा दिनांक 17.12.2021 को एकपक्षीय रूप से अपीलान्ट की गैर हाजिरी मे रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत हुई है। अपीलान्ट अतिक्रमी नहीं है। अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष नोटिस का जबाब प्रस्तुत किया गया है कि अप्रार्थी ने गत खसरा नं० 219 तादादी 20 बीघा 3 बिश्वा पुख्ता मे से 7 बीघा 10 बिश्वा खाम जमीन तारूराम पुत्र गणपतराम से दिनांक 26.06.1968 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदी थी। गत खसरा नं० 219 की जो सीमा थी वह सीमा आज भी कायम है। अप्रार्थी ने जो भूमि क्रय की थी व विक्रेता ने जिसका कब्जा अप्रार्थी को दिया था उसी भूमि पर अप्रार्थी भूमि खरीदने से लेकर आज दिनांक तक कायम है। अप्रार्थी ने कभी कोई सीमा अपने खेत की नहीं बढ़ाई। गत खसरा नं० 219 का अप्रार्थी व तारूराम ने विभाजन कर लिया तथा विभाजन के बाद हाल खसरा नं० 92 रकबा 0.81 हैक्टर अप्रार्थी के खातेदारी काश्तकार मे दर्ज चला आ रहा है। अप्रार्थी की इस खातेदारी जमीन की उत्तरी सीमा मे कदीमी रास्ता था जो राजस्व रिकार्ड मे खसरा नं० 91 गै०मु० रास्ता के रूप मे दर्ज है तथा मौके पर आज भी वहीं कायम है। अप्रार्थी ने हाल खसरा नं० 91 गै०मु० रास्ते की भूमि पर कभी भी अतिक्रमण नहीं किया है तथा रास्ते पर ही कभी अतिक्रमण नहीं किया है तो जोहड पर अतिक्रमण नहीं किया है तथा रास्ते के पश्चिम मे गै०मु० जोहड खसरा नं० 64 स्थित है। जब अप्रार्थी ने रास्ते पर कभी अतिक्रमण नहीं किया है तो जोहड पर अतिक्रमण करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्योंकि जोहड की भूमि से पहले अप्रार्थी की भूमि की ओर उक्त खसरा नं० 91 रास्ता पडता है। पहले अप्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नं० 92 की उत्तरी व पश्चिमी सीमा पर बाड थी जिसे हटाकर अप्रार्थी ने अपने खेत के चारों तरफ रास्ते की तरफ अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि मे पशुओं से अपनी काश्त को बचाने के लिए तारबन्दी कर रखी है तथा अप्रार्थी की कृषि भूमि हाल खसरा नं० 92 रकबा 0.81 हैक्टर की खातेदारी जो अप्रार्थी के नाम दर्ज है। अप्रार्थी की खातेदारी जमीन की कोई

नपति पटवारी हल्का द्वारा नहीं की गई है। अपीलान्त के स्वयं के खेत की सीमा पर खेत की सीमा लिए तारबन्दी कर रखी है। अपीलान्त की मौजूदगी में पटवारी हल्का ने तथाकथित अतिक्रमण को कोई नाम नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्त मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत के आदेश दिनांक 29.09.2022 को अपास्त किया जावे। अपीलान्त विकल्प में यह निवेदन करता है कि अदालत को आदेश दिया जावे अपीलान्त के खेत व खसरा नम्बर 91 व 64 के मध्य की सीमा का अपीलान्त उपस्थिति में सीमाज्ञान किया जाकर अपीलान्त को सीमाज्ञान की प्रति देकर सूचित किया जावे अपीलान्त मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट व नपति के आधार पर स्वयं के खेत की सीमा पर तारबन्दी कर

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेन्ट ने वकील अपीलान्त के कथनों का विरोध करते प्रस्तुत किया कि अपीलान्त ने ग्राम अजाडी कलां स्थित सरकारी भूमि खसरा नम्बर 91 रकबा 0.03 किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से 0.03 है एवं खसरा नम्बर 64 रकबा 12.00 हैक्टर किस्म गै0मु0 जो 0.09 हैक्टर कुल 0.12 है0 भूमि पर तारबन्दी व बाड़ बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। विवादित किस्म गै0मु0 जोहड व गै0मु0 रास्ता है जिस पर अपीलान्त को अतिक्रमण करने का कोई अधिकार अदालत मातहत में अपीलान्त की जबाब देही हुई है। अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत अपीलान्त की यह अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। ने ग्राम अजाडी कलां स्थित सरकारी भूमि खसरा नम्बर 91 रकबा 0.05 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन से 0.03 है एवं खसरा नम्बर 64 रकबा 12.00 हैक्टर किस्म गै0मु0 जोहड में से 0.09 हैक्टर कुल भूमि पर तारबन्दी व बाड़ बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। विवादित भूमि की किस्म गै0मु0 जोहड रास्ता है जिस पर अपीलान्त को अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार की अपीलान्त का अतिक्रमण वैध नहीं माना जा सकता है। अदालत मातहत ने बाद जांच उचित निर्णय किया है। हम अदालत मातहत के निर्णय में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपील खारिज की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.2022 यथावत रखा जावे है। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत को निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावे निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(एल0एस0व
जिला कलक्टर